

गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है अकेले चले।
- अज्ञात

बेटी की परवरिश

80 फीसदी महिलाओं ने बताया कि उन्हें बचपन से ही बात-बात पर कहा गया। आराम से बात करो, प्यार से बात करो, ज्यादा मत बोलो, पलट कर जवाब मत दो और चुप रहो, कहा गया। साथ ही 'जाने दो, क्या फायदा' यह भी बार-बार सुनाया गया।

दीपा नारायण

हमारे देश में सभी पैरेंट्स का मकसद अपनी बेटी की परवरिश एक अच्छी लड़की के रूप में करने की होती है। लेकिन वे करते क्या हैं? वे अपनी बेटियों को दबी-कूचली लड़कियों के रूप में बड़ा करते हैं। इस तरह की परवरिश आगे जाकर उन्हें शोषण का शिकार बनाती है। दरअसल, लड़कियों को बचपन से ही अजस्ट करना सिखाया जाता है। अजस्टमेंट के नाम पर उन्हें बेबस और लाचार बनाया जाता है। इसके उलट लड़कों को प्रबल और ताकतवर बनाकर पाला जाता है। अपने चारों ओर अच्छे और सुंदर कपड़े पहने लोगों, खासकर मिडल क्लास को देखकर लगता है कि दुनिया बदल गई है लेकिन यह बदलाव सिर्फ बाहरी है। अंदर से हम नहीं बदले हैं। 2012 के निर्मया

कांड के बाद मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका मकसद यह जानना था कि यौन हिंसा की जड़ें कहाँ हैं? जब यह पूछा गया कि एक अच्छी लड़की क्या होती है तो युवाओं के जवाब हैरान करने वाले थे। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ये सब पढ़े-लिखे मिडल क्लास लोग थे। इसके बाद यह प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी का सबसे अहम प्रोजेक्ट बन गया।

किसी लड़की को इंसान से 'भूत' बनाने यानी उसके वजूद को नकारने की पहली शुरुआत तब होती है, जब हम उसे बताते हैं कि उसका कोई शरीर नहीं होता। ज्यादातर घरों में शरीर के बारे में बात ही नहीं होती। यही वजह है कि शारीरिक शोषण का शिकार होने के बावजूद लड़कियाँ किसी के सामने मुँह नहीं खोलती, अपनी माँ के सामने भी नहीं। 90 फीसदी

महिलाएँ दूसरों के निगेटिव कमेंट्स की वजह से खुद के शरीर को ही नापसंद करने लगती हैं। इससे उन पर नकारात्मक असर पड़ता है। अब जिसका कोई शरीर नहीं है, तो उसकी आवाज कैसे होगी। 80 फीसदी महिलाओं ने बताया कि उन्हें बचपन से ही बात-बात पर कहा गया। आराम से बात करो, प्यार से बात करो, ज्यादा मत बोलो, पलट कर जवाब मत दो और चुप रहो, कहा गया। साथ ही 'जाने दो, क्या फायदा' यह भी बार-बार सुनाया गया। पढ़ी-लिखी महिलाओं ने भी कहा कि उनकी सबसे बड़ी समस्या चुप रह जाना या किसी के सामने बोल नहीं पाना रहा है। हमेशा दूसरों को खुश रखो, कभी किसी से 'ना' मत कहो, किसी से नाराज मत हो, यही लड़कियों को बचपन से सिखाया और समझाया

जाता है। 25 साल की दर्शा कहती हैं, 'मैं बहुत ही लचीली हूँ। जो दूसरे चाहते हैं, मैं वह आसानी से कर सकती हूँ।' ऐसी सोच के कारण ही लड़कियाँ दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी और पसंद की अनदेखी करती जाती हैं और फैसेल लेने से डरने लगती हैं। हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी यह बताने के लिए काफी है कि सेक्स हमारे लिए कोई नई बात नहीं है लेकिन कोई महिला अपनी सेक्सुअलिटी की बात करे, तो यह वाकई नई बात होती है। लोगों को यह बर्दाश्त नहीं होता कि कोई लड़की या महिला अपनी सेक्सुअल इच्छा या प्राथमिकता के बारे में बात कैसे कर सकती है? जिस महिला को अपने शरीर से प्यार करने का हक नहीं है, उसे सेक्सुअलिटी जाहिर करने का हक कहाँ से होगा?

भरोसा

अशोक वोहरा। हमारे समाज में पुरुषों पर भरोसा ज्यादा किया जाता है। डीयू में विमिन

इम्पावरमेंट पर काम करने वाली रुचि कहती हैं कि मैं महिलाओं पर भरोसा नहीं करती। वे

जलनखोर होती हैं और पीठ पीछे बुराई करती हैं। जब पढ़ी-लिखी महिलाएँ ऐसा कहती हैं तो बाकियों के बारे में क्या कहें? महिलाओं का एकजुट न होना उन्हें हराने या खत्म करने में काफी मदद करता है। महज 15 साल की मुस्कान एक अच्छी लड़की की परिभाषा बताती हैरू दयालु, सौम्य, बिना शर्त दूसरों की मदद करने वाली, प्यार करने वाली, अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करने वाली उपफ। काफी थकानेवाली है यह लिस्ट। जिम्मेदारियों को पूरा करते-करते अपनी सारी चाहतें पीछे छूट जाती हैं। अपने हर काम के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना, महिलाओं को और कमजोर करता है।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

सम्मान और सुरक्षा

मीडिया कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में लोगों को सचेत एवं जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है घलाक डाउन के कारण अगर कहीं गरीब तबके के लोगों को कठिनाई हो रही है तो कई बार मीडिया के माध्यम से ही सरकारों को उसकी जानकारी मिली है और सरकार ने उन कठिनाईयों को दूर किया है। विगत दिनों ऐसा ही एक उदाहरण दिल्ली में देखने को मिला था घलाकडाउन के कारण दिल्ली में बहुत से गरीब मजदूर यमुना नदी पर पुल के नीचे दयनीय हालत में दिन गुजार रहे थे, घउन्हें पेट भरने के लिए ठीक से भोजन भी नसीब नहीं हो रहा था। एक समाचार चैनल द्वारा इस खबर को प्रसारित किए जाने के बाद कुछ ही घंटों के अन्दर सरकार की बसें वहाँ पहुंच गई और उनके द्वारा मजदूरों की सुरक्षित स्थानों पर न केवल रहने की व्यवस्था कर दी गई बल्कि उन्हें नियमित भरपेट भोजन भी मिलने लगा इसलिए यह सोचना गलत है कि मीडिया केवल आलोचना करता है घ देश के विभिन्न हिस्सों में विस्थापित गरीब मजदूरों की कठिनाईयों को दूर करने में मीडिया महत्व पूर्ण भूमिका रहा है। कोरोनावायरस के संक्रमण के खतरों के प्रति लोगों को सचेत करने में मीडिया सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा हैघकोरोना वायरस के प्रकोप के कारण अनेक राज्यों के कई शहरों, जिलों यहां तक कि राज्यों की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है ऐसे स्थानों पर मीडिया कर्मियों को जाने की अनुमति है ताकि वे मौके पर मौजूद रहकर वहां की वास्तविक स्थिति की जानकारी एकत्र करके उसे समाचार पत्रों अथवा दूरदर्शन के माध्यम से हम तक पहुंचा सकें।

जाहिर है, इस कदम का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो अस्थायी तौर पर अमेरिका में काम के लिए आए हुए हैं। जो लोग एच-1बी जैसे नॉन इमिग्रेशन वीजा पर रह रहे हैं, उन पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

फैसेल पर विरोध

अमर सिन्हा

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने प्रवासी प्रफेशनल्स को निशाने पर लेते हुए अमेरिका फर्सट का राग अलापा है और नए ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध स्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर अगले 60 दिन के लिए रोक लगा दी है।

बकौल ट्रंप, कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा है उसे ध्यान में रखते हुए यह कदम अमेरिकी श्रमिकों की नौकरियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। यह भी कि नए आब्रजकों पर इस रोक से अहम चिकित्सा संसाधनों को अमेरिकी नागरिकों के लिए बचाकर रखने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि इस व्यवस्था में कुछ छूट जरूर रहेगी लेकिन रोक भी दो महीने से आगे बढ़ाई जा सकती है। जाहिर है, इस कदम का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो अस्थायी तौर पर अमेरिका में काम के लिए आए हुए हैं। जो लोग एच-1बी जैसे नॉन इमिग्रेशन वीजा पर रह रहे हैं, उन पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

नौकरी जाने के दो महीने बाद इन लोगों को देश छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन इस मामले में अभी अंतिम शब्द कहा जाना बाकी है। चिकित्सा कर्मियों या निवेश श्रेणी के तहत नागरिकता का



आवेदन करने वालों को दो महीने की इस रोक के दौरान भी ग्रीन कार्ड दिए जा सकते हैं। ट्रंप के इस फैसले पर अमेरिका में विरोध देखा गया है।

विपक्षी डेमोक्रेट्स का कहना है कि कोरोना वायरस से निपटने में नाकामी और नवंबर में होने वाले चुनाव से ध्यान हटाने के लिए यह कदम उठाया गया है। कांग्रेस की अनुसंधान सेवा की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार करीब 10 लाख वैध विदेशी कामगार और उनके परिवार ग्रीन

कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इस फैसले का असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा। ग्रीन कार्ड देने के मौजूदा नियमों में भारी बदलाव के लिए अमेरिकी सीनेटर डिक डर्बिन द्वारा लाए गए एस 386 संशोधन को लेकर भारतीय समुदाय पहले से ही डरा हुआ है। इफोसिस, विप्रो, टीसीएस आदि दिग्गज भारतीय आईटी कंपनियों के विदेशों से होने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। अभी तकरीबन 100 भारतीय कंपनियां अमेरिका में काम करती हैं, जिनके कर्मचारियों के लिए ग्रीन कार्ड बहुत बड़ा मुद्दा है। यह फैसला इनका कारोबार चौपट कर सकता है लिहाजा भारत सरकार को आधिकारिक स्तर पर इस मुद्दे को उठाना ही चाहिए। यह इस बात की साफ अनदेखी रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इस ऊंचाई तक ले जाने में प्रवासियों का बड़ा योगदान रहा है।

संकट की इस घड़ी में वे जी-जान लगाकर पुश्तैनी अमेरिकियों के साथ खड़े हैं और अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका होगी। अमेरिका को समझना चाहिए कि हर किसी से मोर्चा खोलकर वह इस संकट से नहीं निपट सकता। सालों से अमेरिकी नागरिकता की उम्मीद में काम किए जा रहे लोगों को इस तरह हवा में खड़ा कर देना अपने श्रेष्ठ संसाधनों से पीछा छुड़ा लेने जैसा ही है।

सूडोकू नवताल-5333		****			
7	4	6	1	8	2
5		8	7		
9		6			
6		7	9	5	3
5		4			1
3	1	8	2	7	
		5			6
		4	3	9	
4	3	2	1	5	7

अपना ब्लॉग

जोखिमों में इजाफा हो जाता है

मोहन। रेड जोन और ऑरेंज जोन में आने वाले ऐसे संवेदनशील इलाकों में भी जाने से मीडिया कर्मियों परहेज नहीं करते जहां पुलिस, चिकित्सक, पेरामेडिकल स्टाफ के सदस्य भी इस आशंका के साथ जाते हैं कि उन पर वहां हमला भी हो सकता है। चिकित्सकों, पेरामेडिकल स्टाफ के सदस्यों और पुलिस बल की भांति मीडिया कर्मियों अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन एक मिशन के रूप में कर रहे हैं घ ऐसा नहीं है कि उनको अपनी जिम्मेदारियों के निष्ठापूर्वक निर्वहन के मार्ग में किन्हीं कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है परंतु अपने कर्तव्य पालन के प्रति समर्पण की भावना उन्हें बड़े से बड़े जोखिम उठाने का साहस और आत्मविश्वास भी प्रदान करती है। मीडिया जब यह तय कर लेता है कि वह सच रहेगा और सच के सिवा कुछ नहीं करेगी तो उसके जोखिमों में इजाफा हो जाता है।

ट्रेन नहीं... अर्थव्यवस्था पटरी पर लाना है...

